an>

Title: Need to conduct an enquiry into the alleged tax evasion issue in Panama papers case.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य पहर में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज तक के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश पनामा पेपर लीक मामले में हुआ है। यह घोटाला कुछ पत्रकारों द्वारा 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो पनामा की कानूनी कंपनी मोसाक फोनसिका है उसके कंप्यूटर से निकाला गया है। यह कंपनी पूरे विश्व के करोड़पतियों को टैक्स चोरी करने के तरीके बताने और देश से बाहर पैसा जमा कराने का काम कर रही है। अभी तक के छानबीन में अपने देश के करीब 500 लोगों का नाम उजागर हुआ है। जैसे -जैसे छानबीन हो रहा है नामों की संख्या बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि सरकार का इस विषय पर क्या दायित्व है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों का नाम उजागर किया जाए। अभी तक सरकार की कार्रवाई से पता नहीं चल पाया है कि सरकार इस विषय पर कितना गंभीर है। आरबीआई गवर्नर का एक बयान विरोधाभासी है, वह कहते हैं कि अमीरों की कमाई पर प्रश्न उठाना सही नहीं है। आरबीआई नियम के तहत ही यह पैसा बाहर गया है, यह कैसा कानून है कि कोई करोड़पति 2,50,000 डॉलर सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर कहीं भी बाहर ट्रांसफर कर सकता है, इसके साथ ही उनके आश्रितों और बच्चों के नाम से अलग-अलग इतनी धनराशि ट्रांसफर कर सकता है। आरबीआई उसी कानून को सही ठहरा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्न गलत सही का नहीं है। प्रश्न है टैक्स चोरी का, धोखाधड़ी का है और देश से **गद्दारी** का है, यह क्राइम है। ऐसे लोगों के साथ सरकार कभी भी समझौता न करे और कार्रवाई करे। काले धन के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई लेकिन आज तक देश में कालाधन नहीं आया इसके लिए भी सरकार तत्परता से काम करे।